this M.G. network is adequately handling the traffic offered. However, a new B.G. railway line Jogighopa-Guwahati (142 km) with a rail-cum-road bridge across the river Brahmaputra at Jogighopa at a cost of Rs. 444 crores has already been taken up. A sum of Rs. 85 crores was allocated for this project in 1990-91.

Comprehensive Agricultural Policy

*6. SHRI SOM PAL:
SHRI CHIMANBHAI MEHTA:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government propose to declare floor prices for major agricultural commodities in view of arrival of monsoons; and

(b) whether Government also propose to submit a comprehensive agricultural policy in the current session of Parliament?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI BALRAM JAKHAR): (a) Proposals for the procurement/ minimum support prices for Kharif crops of 1991-92 as received from the Commission for Agricultural Costs and Prices are under the consideration of the Government. These would be announced very early.

(b) No, Sir.

राजस्थान में सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान किया जाना

*7. **डा० अबरार अहमद** : क्या **जल-संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान की कौन-कौन सी सिंचाई योजनाएं केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं तथा उन्हें कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है और उन पर कितनी-कितनी धनराशि खर्च किए जाने का अनुमान है,

(ख) राजस्थान की ऐसी कौन-कौन सी सिंचाई परियोजनाएं हैं जो केन्द्रीय सरकार की सहायता से चलाई जा रही हैं किन्तु अभी पूरी नहीं हुई हैं तथा उसके क्या कारण है, और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को राजस्थान में चल रहीं सिंचाई योजनाओं मे व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई है, यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या हैं तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० सी० शुक्ल) : (क) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

(ख) इंदिरा गांधी नहर परियोजना चरण-II को सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता दी गयी है । परियोजना को नवीं योजना से आगे ले जाए जाने का कार्यक्रम हैं । चरण-II क्षेत्र में स्थिति अधिक ठीक नहीं हैं तथा सड़क पेयजल आपूर्ति, वनरोपण जैसी अवसंरचना का विकास नहर निर्माण के साथ किया जाना है जो कि अवसंरचना कार्यों से आगे हैं, ताकि अधिवासी वहां जा सकें, क्षमता का उपयोग शीघ्र प्राप्त किया जा सके तथा नहर प्रणालियों में उड़ने वाली रेत से रखरखाव की समस्याएं उत्पन्न न हों ।

(ग) जी, नहीं ।

विवरण

केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान किया जाना तथा उन पर होने वाला अनुमानित खर्चा

क्रम सं०	परियोजना का नाम	मूल्यांकन की स्थिति	मार्च, 1991 के अंत तक प्रत्याशित व्यय
			(करोड़ रुपये में)
	क. वृहद		
1	जयसमुन्द आधुनिकीकरण	राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त सूचना भेजी जानी है।	1.96
2	नर्मदा नहर	परामर्शदात्री समिति की होने वाली अगली बैठक में टिप्पणी प्रस्तुत करने के वास्ते परामर्शदात्री समिति के वास्ते टिप्पणी को 6/91 में अंतिम रूप दे दिया था।	3.13
	ख. मध्यम		
3	गारदा सिंचाई	राज्य को केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरण की टिप्पणियों की अनुपालना करनी है।	—
4	बान्दी सेन्टा	—वही—	—
5	सुकली	—वही—	—
6	गंभीरी आधुनिकीकरण	परियोजना का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन किया गया है। राज्य सरकार को निधियों के आवंटन पर योजना आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना करनी है।	4.60

Cauvery Water Distribution

*8. SHRI DEBABRATA BISWAS: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state the details of the arrangements made between Karnataka and Tamil Nadu on Cauvery water distribution?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI V. C. SHUKLA): The Cauvery Water Disputes Tribunal has directed the State Government of Karnataka to release water from its reservoirs in Karnataka so as to ensure that 205 T.M.C. (Thousand Million Cubic Feet) of water is available in Tamil Nadu's Mettur Reservoir in a year from June to May. According to the order of the Tribunal this arrangement is to remain operative till the final adjudication of the dispute referred to the Tribunal.